

मामलों का विवरण

मेसर्स हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड v.

मेसर्स नेशनल हाईवेयस अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सिविल अपील सं.)।4658 2023 का)

24 अगस्त, 2023

[एस. रवींद्र भाट और अरविंद कुमार, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: यह मुद्दा एक अनुबंध शर्त की व्याख्या के संबंध में है, जिसमें मिट्टी या तालाब के साथ तटबंध निर्माण के लिए भुगतान के लिए उपयोग की जाने वाली मात्राओं की माप की आवश्यकता होती है; और मध्यस्थों की असहमत राय की प्रासंगिकता।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996।34, 37 - मध्यस्थ पुरस्कार-हस्तक्षेप का दायरा यू/एस. एस.34 और 37-तथ्यों पर, तीन तकनीकी सदस्य मध्यस्थता ने एक पुरस्कार पारित किया जो अधिकांश प्रश्नों पर सर्वसम्मत था, जबकि अन्य पर, एक असहमत विचार था-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने माना कि न्यायाधिकरण की बहुमत राय ने एक प्रशंसनीय और उचित दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित किया, हालांकि, खंड पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायाधिकरण की बहुमत राय और पुरस्कार अनुबंध की एक अविश्वसनीय व्याख्या पर आधारित थे, पुरस्कार को दरकिनार कर दिया-शुद्धता:

आयोजित किया गया: जिन पुरस्कारों में कारण होते हैं, विशेष रूप से जब वे संविदात्मक शर्तों की व्याख्या करते हैं, उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, हल्के ढंग से-किसी पुरस्कार की जांच के मानक के बारे में प्रचलित दृष्टिकोण-न्यायिक समीक्षा नहीं, विवाद करने वाले व्यक्तियों द्वारा उनके निर्णयों के आधार पर-और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, एक छोटे से क्षेत्र को छोड़कर जहां यह स्थापित किया जाता है कि ऐसा दृष्टिकोण पेटेंट अवैधता या हस्तक्षेप के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए तथ्यों या शर्तों की उनकी व्याख्या, विकृत, पर आधारित है-न्यायाधीश एक सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं; आमतौर पर, अपीलीय समीक्षा के लिए सराहना की जाती है, हालांकि, यू/एस के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय यह उपलब्ध नहीं है।34 - न्यायालय, प्राथमिक अनुबंध व्याख्या की प्रक्रिया के माध्यम से, इस प्रकार, अनुबंध के लिए मार्ग नहीं बना सकते हैं।

623 624

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

ऐसी समीक्षा जो यू/एस द्वारा निषिद्ध है।34 - इस प्रकार, अपीलीय समीक्षा के लिए खंड पीठ का दृष्टिकोण, यू/एस।37, और उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के परिणामस्वरूप न्यायाधिकरण के बहुमत के दृष्टिकोण को विस्थापित किया गया, साथ ही सर्वसम्मत दृष्टिकोण भी-जब तक बहुमत द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण प्रशंसनीय था और अन्यथा रखने का कोई कारण नहीं है, इस तरह का प्रतिस्थापन अस्वीकार्य था-उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को दरकिनार कर दिया जाता है-पुरस्कार, जो चुनौती का विषय थे, और जिस हद तक उन्हें दरकिनार कर दिया गया था, उन्हें बरकरार रखा जाता है और बहाल किया जाता है।[पारस 22,23,28]

मध्यस्थता-मध्यस्थता पुरस्कार-मध्यस्थ की असहमतिपूर्ण राय-इसकी प्रासंगिकता -

आयोजित किया गया: असहमति की राय को एक पुरस्कार के रूप में नहीं माना जा सकता है यदि बहुमत पुरस्कार को अलग कर दिया जाता है-यह उस स्थिति में उपयोगी सुराग प्रदान कर सकता है जब कोई प्रक्रियात्मक मुद्दा होता है जो चुनौती के दौरान महत्वपूर्ण हो जाता है-जब पीड़ित पक्ष द्वारा बहुमत पुरस्कार को चुनौती दी जाती है, तो अदालत और पीड़ित पक्ष का ध्यान बहुमत पुरस्कार में त्रुटियों या अवैधताओं को इंगित करना होता है-अल्पसंख्यक पुरस्कार या असहमति की राय केवल मध्यस्थ के विचारों को मूर्त रूप देती है जो बहुमत से असहमत होते हैं-बहुमत पुरस्कार से पीड़ित पक्ष के लिए कोई अवसर नहीं होता है, या, अधिक महत्वपूर्ण रूप से, बहुमत पुरस्कार में सफल होने वाली पार्टी, असहमति की राय में दृष्टिकोण या निष्कर्ष में दृढ़ता, संभाव्यता, अवैधता या विकृति को चुनौती देने के लिए-असहमति -[पैरा 27]

शहरों और अन्य
संदर्भों की सूची

एसोसिएट बिल्डर्स बनाम दिल्ली विकास निगम [2014] 13 एससीआर 895; बीओसी इंडिया लिमिटेड बनाम। भगवती ऑक्सीजन लिमिटेड [2007] 3 एससीआर 915; इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम श्री गणेश पेट्रोलियम राजगुरुनगर [2022] 16 एससीआर 450; पीएसए एस. आई. सी. ए. एल. टर्मिनल्स प्रा. लिमिटेड वी.वी. ओ. के न्यासी मंडल चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट [2021] 5 एस. सी. आर. 408; साउथ ईस्ट एशिया मरीन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड (एस. ई. ए. एम. ई. सी. लिमिटेड) बनाम ऑयल इंडिया लिमिटेड [2020] 4 एस. सी. आर. 254; एम/एस. वायस्टाल्पाइन शियनन जीएमबीएच बनाम डीएमआरसी [2017] 1 एससीआर 798; दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस (पी) लिमिटेड बनाम डीएमआरसी [2021] 5 625

मैसर्स हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम मैसर्स नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया

एस. सी. आर. 984; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम संबद्ध निर्माण [2003] पूरक 2 एस. सी. आर. 55; मैकडरमोट इंटरनेशनल इंक. बनाम। बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड [2006] सप्लीमेंट। 2 एस. सी. आर. 409; एम. एस. के. प्रोजेक्ट्स (आई) (जे. वी.) लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य [2011] 9 एस. सी. आर. 402; दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड बनाम। नेविगेंट टेक्नोलॉजीज (पी) लिमिटेड [2021] 1 एससीआर 1135; सांगयोंग एंग। & निर्माण कंपनी लिमिटेड

v. एनएचआई [2019] 7 एससीआर 522-संदर्भित।

डेविड सेंट जॉन सटन, जूडिथ गिल और मैथ्यू गियरिंग क्यूसी,

मध्यस्थता पर रसेल, 24 वीं संस्करण। (स्वीट और मैक्सवेल), पी. 313; गैरी बोर्न,

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता, वोल्टर्स क्लूवर, एडन। 2009, वॉल्यूम।

II, पी. 2466 और 2469-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: 2023 की सिविल अपील सं. 4658।

2012 के एफ. ए. ओ. संख्या 48 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 08.11.2012 के निर्णय और आदेश से। सह

2023 की सिविल अपील संख्या 4659, 4660, 4661 और 4662।

रूप:

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए. एस. जी., अनिल ऐरी, डॉ. ए. एम. सिंघवी, वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता।, मोहित डी. राम, रवि कृष्ण चंदना, सुश्री मोनिशा हांडा, सुश्री बिंदिया लोगावनी, अनुभव शर्मा, मुदित रुहेल्ला, समीर पारेख, सुमित गोयल, सुश्री श्रीपर्णा बसाक, प्रतीक खंडेलवाल, जयंत बजाज, मैसर्स पारेख एंड कंपनी, महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, सुश्री श्रुति अरोड़ा, अनिरुद्ध भाटिया, देवांश श्रीवास्तव, निधि राम, राहुल नारंग, सुश्री विदिशा स्वरूप, ई. सी. अग्रवाल, जॉर्ज थॉमस, डॉ. स्वरूप जॉर्ज, आर. सतीश, राजेश कुमार, मोहन दास के. के., माथेन जोसेफ, श्रीमती एस. गीता, मैसर्स एस. उपस्थित दलों के लिए।

626 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

न्यायाधीश एस. रवींद्र भाट, जे.

1. इन सभी अपीलों में एक अनुबंध शर्त की व्याख्या के संबंध में एक सामान्य प्रश्न पर निर्णय शामिल है, जिसमें मिट्टी या तालाब की राख के साथ तटबंध निर्माण के लिए भुगतान के लिए उपयोग की जाने वाली मात्राओं की माप की आवश्यकता होती है। दावेदारों (इसके बाद "ठेकेदारों") ने तर्क दिया कि उपाय एक और समान है, जो पूरे तटबंध के रूप में एक समग्र क्रॉस सेक्शन लेकर और औसत अंत क्षेत्र विधि द्वारा मात्रा का निर्धारण करके है। हालांकि, पर्यवेक्षण इंजीनियर (इसके बाद "ई. ई.") ने एक विधि अपनाई, जिसके तहत दो अलग-अलग वस्तुओं में तटबंध की मात्रा के निर्धारण के लिए मिट्टी और तालाब की राख द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र के लिए क्रॉस सेक्शन के क्षेत्र को विभाजित किया गया था। ठेकेदार ने आग्रह किया कि यह तकनीकी विशिष्टता (इसके बाद "टी. एस.") खंड 305.8 के विपरीत था; भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (इसके बाद "एन. एच. ए. आई.") ने ई. ई. की व्याख्या को उचित ठहराया। चूंकि इन सभी अपीलों में अलग-अलग परिणाम आए हैं, और उनमें से कुछ में विवादित निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ के सीए 4658/2023 1 (जिसे इसके बाद "मुख्य निर्णय" के रूप में संदर्भित किया गया है) के फैसले पर निर्भर हैं, उस अपील में तथ्यों और निर्णयों का उल्लेख किया जाएगा।

2. एनएचआई ने ठेकेदार को यू. पी. में इलाहाबाद उप-मार्ग परियोजना के निर्माण का काम दिनांक 02.06.2004 के समझौते द्वारा प्रदान किया। परियोजना पूरी हो गई। हालांकि, अनुबंध के विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में पक्षों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुए; इन्हें मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया गया था। एन. एच. ए. आई. के पास एक अंतर्निर्मित समाधान तंत्र है, अर्थात् एक विवाद समाधान बोर्ड ("डी. आर. बी.") जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं, जिन मामलों को पहले संदर्भित किया जाता है। चूंकि ठेकेदार डी. आर. बी. की राय से संतुष्ट नहीं था, इसलिए समझौते के संदर्भ में, वह मध्यस्थता का आह्वान कर सकता था और कर सकता था। वर्तमान मामले में विवादों का समापन तीन तकनीकी व्यक्तियों के मध्यस्थता के संदर्भ में हुआ, जिन्होंने प्रतिद्वंद्वी दृष्टिकोण और उनके सामने की सामग्री पर विचार करने के बाद निर्णय दिया। अधिकांश प्रश्नों पर पुरस्कार सर्वसम्मत था, जबकि अन्य प्रश्नों पर मध्यस्थों में से एक का असहमतिपूर्ण विचार था।

1 एस. एल. पी. सं. 38162/2012 से बाहर निकलते हुए, जिसे एफ. ए. ओ. (ओ. एस.) सं. 48/2012 में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ के दिनांक 08.11.2012 के फैसले के खिलाफ निर्देशित किया गया था। 2 पुरस्कार दिनांक 30.03.2010 627

मेसर्स हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड v.

मैसर्स नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया [एस. रवींद्र भारत, जे.] 628 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

3. सर्वसम्मत दृष्टिकोण और बहुमत दृष्टिकोण दोनों से व्यथित ठेकेदार ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ("अधिनियम") की धारा 34 के तहत आपत्तियों को प्राथमिकता दी। एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिका को खारिज कर दिया। एकल न्यायाधीश की यह सुविचारित राय थी कि जहां तक माप पहलुओं का संबंध है, न्यायाधिकरण की बहुमत राय ने एक प्रशंसनीय और उचित दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित किया जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी:

"26. जहाँ तक विवाद 2 और 4 का विषय बनने वाले तटबंध के निष्पादित कार्य के लिए भुगतान न करने का संबंध है, यह विशुद्ध रूप से माप पर आधारित तथ्य का प्रश्न है। मद 2 के अंतर्गत आने वाले तटबंध के निर्माण के संबंध में कोई विवाद नहीं है। बी. ओ. क्यू. का 02 (ए)। वास्तव में, एनएचआई पहले ही उक्त निर्माण के लिए एचसीसी का भुगतान कर चुका है। एम. ओ. आर. टी. एच. टी. एस. के खंड 305.8 में तटबंध के क्रॉस सेक्शन को एक पूरे समग्र खंड के रूप में मापने का प्रावधान है और मद संख्या 2 (बी) के तहत भुगतान किया गया है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण के बहुमत सदस्यों का निर्णय उनके सामने मौजूद सामग्री के विश्लेषण के आधार पर लिया जाना एक संभावित दृष्टिकोण था। केवल इसलिए कि एक अन्य दृष्टिकोण जैसा कि असहमत राय से प्रमाणित होता है, अधिनियम की धारा 34 के तहत इस न्यायालय द्वारा संभावित हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।"

4. एन. एच. ए. आई. ने डिवीजन बेंच में अपील की, जिसने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को दरकिनार कर दिया, और कहा कि न्यायाधिकरण का बहुमत दृष्टिकोण, और निर्णय, अनुबंध की एक अविश्वसनीय व्याख्या पर आधारित थे। यह अभिनिर्धारित आदेश में अभिनिर्धारित किया गया था कि:

"[.....] तकनीकी विनिर्देशन के बी. ओ. क्यू. मद सं. 02 और खंड 305.8 के संयुक्त पठन पर, हमारे लिए, यह स्पष्ट है कि उपयोग की जाने वाली विभिन्न सामग्री, यानी मिट्टी और तालाब की राख के संबंध में अनुभागों को लिया जाना चाहिए। विशेष

रूप से, यह उत्तरदाताओं का मामला नहीं है कि दोनों को एक मिश्रण में मिलाया जाता है और फिर उपयोग किया जाता है। मिट्टी और तालाब की राख का अलग से उपयोग किया जाता है। इस प्रकार, क्रॉस सेक्शन को अंतराल पर लिया जाना चाहिए। हम प्रत्यर्थी को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दे सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन में दो सामग्रियों की मात्रा की गणना करना संभव नहीं है, जब 30 महीनों के लिए अपीलार्थी और प्रत्यर्थी दोनों वास्तव में उसी के अनुसार माप कर रहे थे। प्रत्यर्थी ने स्वयं आई. पी. सी. बनाए और भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जो अपीलार्थी द्वारा विधिवत भुगतान किए गए थे। इस तरह

3 दिनांकित 30.11.2011 आदेश के अनुसार

माप दोनों सामग्रियों के वास्तविक उपयोग के आधार पर किए गए थे। हम इस बात की सराहना करने में विफल हैं कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकता था कि दोनों वस्तुओं को अलग-अलग मापने का तरीका अनुबंध के अनुसार नहीं था। ऐसा लगता है कि आम सहमति के सिद्धांतों पर ध्यान देने के बाद बहुमत का दृष्टिकोण इस महत्वपूर्ण मुद्दे की सराहना करने में विफल रहा है। [.....]”

दलों की दलीलें

5. अपीलार्थी/ठेकेदारों की ओर से डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, श्री वी. गिरि और श्री अनिल ऐरी, विद्वान वरिष्ठ वकीलों, श्री समीर पारेख और श्री जॉर्ज थॉमस विद्वान वकीलों ने प्रस्तुतियाँ दीं। यह तर्क दिया गया कि विवादित निर्णय अधिनियम की धारा 34/धारा 37 के तहत अधिकार क्षेत्र के दायरे से बहुत आगे जाता है। डिवीजन बेंच ने इस आधार पर निर्णय में हस्तक्षेप करते हुए कि उसने किया, अधिनियम की धारा 37 के तहत हस्तक्षेप के अत्यंत संकीर्ण दायरे का उल्लंघन किया। यह तर्क दिया गया था कि इस अदालत ने कई मामलों में यह अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम का उद्देश्य मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती देने के आधार को न्यूनतम तक सीमित करना है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय ने बार-बार यह अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालयों का सामान्य दृष्टिकोण निर्णय और मध्यस्थता निर्णय को बरकरार रखना होना चाहिए और निर्णय में खामियों, विसंगतियों और दोषों को चुनने के लिए सावधानीपूर्वक कानूनी नजर रखने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

6. यह तर्क दिया गया था कि माप की एक विधि से संबंधित संविदात्मक शर्तें तकनीकी समझ पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं और इसे अनुबंध के सामान्य प्रावधान की तरह पढ़ा और व्याख्या नहीं की जा सकती है। उनके विचारों के आधार पर समय के साथ उनके अर्थ विकसित हुए हैं और अदालतों को तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा दिए गए निर्णय को टालना चाहिए। यह तर्क दिया गया था कि विवाद का विशिष्ट बिंदु यह था कि क्या 'निर्माण' के कारण कोई बकाया राशि है।

तकनीकी विनिर्देशनों के खंड 305.2.2,3 के साथ पठित बी. ओ. क्यू. मद संख्या 2 (बी) के अनुसार तालाब की राख के साथ तटबंध का भुगतान करना देय था।

ठेकेदार। यह विशुद्ध रूप से तथ्य का सवाल था, जिस पर पुरस्कार की बारीकियों को छोड़ देना पड़ता था। वकील ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कई अपीलों में, डी. आर. बी. ने एन. एच. ए. आई. द्वारा एक आंतरिक तंत्र का गठन किया, जिसमें पूरी तरह से तकनीकी कर्मी शामिल थे, जिन्हें उसके (एन. एच. ए. आई.) द्वारा नामित किया गया था, उन्होंने भी राय का समर्थन किया था, जो ठेकेदारों की व्याख्या का समर्थन करता था। इस पृष्ठभूमि और मध्यस्थता में दी गई समान व्याख्या को देखते हुए, न्यायाधिकरण द्वारा, जिसमें फिर से विशेषज्ञ शामिल थे, हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं थी।

मेसर्स हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड v.

629

मैसर्स नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया [एस. रवींद्र भाट, जे.] 630

7. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विवादित निर्णय विफल रहा या इस बात की अनदेखी की कि दो प्रकार के तटबंध हैं—एक मिट्टी के साथ और दूसरा, राख और मिट्टी के साथ। इसलिए, ठेकेदार ने इन दो प्रकार के तटबंधों के लिए दरें उद्धृत की थीं।

8. इस बात पर प्रकाश डाला गया कि एम. ओ. आर. टी. एच. 4 के खंड 305 तकनीकी विशिष्टताओं को परियोजना विशिष्टताओं के साथ पढ़ा जाता है और अतिरिक्त तकनीकी विशिष्टताओं में निहित सी संशोधनों से दो प्रकार के तटबंध बनते हैं, अर्थात् मिट्टी के साथ तटबंध और तालाब की राख के साथ तटबंध, उपरोक्त दो प्रकारों में से प्रत्येक के लिए सामग्री की आवश्यकताओं को खंड 305.2.2.2 (मिट्टी के लिए) और 305.2.2.3 (तालाब की राख के लिए) अतिरिक्त तकनीकी विशिष्टताओं के खंडों में निर्दिष्ट किया गया है।

9. वकील ने प्रस्तुत किया कि इसके अलावा, विवादित निर्णय ने इस बात की अनदेखी की कि एम. ओ. आर. टी. एच. का टी. एस. खंड 305 केवल मिट्टी के साथ तटबंध से संबंधित है; इसलिए एक परियोजना विशिष्ट उप-खंड 305.2.2,3।2 निर्माण कार्यों को अनुबंध में शामिल किया गया था जो विभिन्न कार्यों को निर्दिष्ट करता है (अर्थात्, तालाब की राख के साथ तटबंध के लिए ठेकेदार द्वारा पालन की जाने वाली ऊपरी मिट्टी की स्थापना, हटाने और भंडारण, भूमि को सहारा देने वाले तटबंध को संकुचित करना, फैलाने वाली सामग्री, संघनन, फिशिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, भुगतान के लिए एक माप आदि)। यह प्रस्तुत किया गया था कि खंड 305.2.2,3।2 आगे कहा गया है, "कार्य खंड 4.7 के अनुरूप होगा। आई. आर. सी. एस. पी.:58 - 2001"। यह रेखांकित किया गया कि अनुबंध में बी. ओ. क्यू. 5 मद 2 (ए) में 'मिट्टी के साथ मिट्टी के तटबंध के निर्माण' और बी. ओ. क्यू. मद 2 (ए) में 'तालाब की राख के साथ तालाब की राख के तटबंध के निर्माण' के लिए भुगतान पर विचार किया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि बी. ओ. क्यू. अनुबंध आवश्यकताओं के अनुपालन में काम की पूरी वस्तु के निष्पादन और समापन से संबंधित है और यह केवल काम के निष्पादन में उपयोग की जाने वाली किसी भी व्यक्तिगत सामग्री/उपभोग्य सामग्रियों से संबंधित नहीं है।

10. यह तर्क दिया गया था कि अनुबंध की शर्तों और शर्तों को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए; इस प्रकार, तकनीकी विशिष्टताएं, चित्र और अन्य दस्तावेज अनुबंध का हिस्सा हैं जिन पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता है। वकील ने इस बात पर भी जोर दिया कि बी. ओ. क्यू. की प्रस्तावना और तकनीकी विशिष्टताओं को एक साथ पढ़ने पर यह भी अनिवार्य हो जाता है कि दी गई करें

4 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 5 राशि का बिल

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

बी. ओ. क्यू. मद में 2 (ए) और (बी) तटबंध अर्थात् मिट्टी के तटबंध और तालाब की राख के तटबंध के निर्माण के लिए हैं न कि तटबंध में सामग्री के उपयोग के लिए। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि पुरस्कारों में हस्तक्षेप के लिए लागू परीक्षण एसोसिएट बिल्डर्स बनाम में स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया था।

दिल्ली विकास निगम ("इसके बाद", सहयोगी बिल्डर ") 6 और

विवादित फैसले द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था। वकील ने बीओसी इंडिया लिमिटेड बनाम बीओसी इंडिया लिमिटेड पर भी भरोसा किया। भगवती ऑक्सीजन लिमिटेड 7 ने आग्रह किया कि चूंकि न्यायाधिकरण ने अनुबंध की व्याख्या पर एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण पर भरोसा किया था, इसलिए अदालत के लिए पुरस्कार को रद्द करने के लिए खुला नहीं था।

11. सुश्री ऐश्वर्या भाटी को पता चला कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ए. एस. जी.) एन. एच. ए. आई. की ओर से पेश हुई और अदालत से उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और उसके बाद के अन्य फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करने का आग्रह किया, जो इन सभी अपीलों का विषय हैं। उन्होंने तर्क दिया कि पुरस्कार में खंड पीठ का हस्तक्षेप न्यायसंगत और न्यायसंगत था। विद्वान वकील ने शर्तों में अंतर पर प्रकाश डाला क्योंकि वे अनुबंध में मौजूद थे, जो कि बहुमत पुरस्कार में उद्धृत किया गया था, जो कि विवादित निर्णय में अपील का विषय है। यह तर्क दिया गया कि खंड को गलत तरीके से पुनः प्रस्तुत किया गया था और इसके परिणामस्वरूप, न केवल गलत व्याख्या द्वारा दूषित किया गया था, बल्कि न्यायाधिकरण द्वारा अनुबंध की शर्तों को फिर से लिखने का मामला था। इसका मतलब था कि न्यायाधिकरण ने अनुबंध की शर्तों से परे काम किया। विद्वान वकील ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह का पुनर्लेखन डिवीजन बेंच के लिए पुरस्कार में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त न्यायसंगत कारण था। इस पहलू को नजरअंदाज कर दिया गया था-यहां तक कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भी अनदेखी की गई थी।

12. इसके बाद यह तर्क दिया गया कि ठेकेदारों और न्यायाधिकरण द्वारा की गई व्याख्या, यदि स्वीकार की जाती है, तो जहां तक तटबंध में उपयोग की जाने वाली मिट्टी और तालाब की राख के अनुपात का संबंध है, बेतुके परिणाम सामने आएंगे। ये घटक या सामग्री मामले-दर-मामले भिन्न होती हैं। इसलिए, काम के लिए उपयोग की जाने वाली मिट्टी और तालाब की राख की परवाह किए बिना एक दर पर भुगतान करने के लिए एनएचआई पर दायित्व डालना अतार्किक और अनुचित होगा। विद्वान वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि तटबंध निर्माण में ऐसी सामग्रियों के विभिन्न अनुपात शामिल हो सकते हैं-9 से लेकर:1 3 तक:2 विभिन्न स्थानों पर। इसलिए, प्रभाग

6 2014 [13] एससीआर 895 7 2007 [3] एससीआर 915 631

मेसर्स नेशनल हाईवाइज ऑथोरिटी ऑफ इंडिया 632 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

पीठ ने सही निर्णय दिया कि एनएचआई पर इस दायित्व को डालना उचित नहीं होगा।

13. इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि न्यायाधिकरण और विद्वान एकल न्यायाधीश ने अनुबंध की शर्तों और शर्तों का अनुचित विश्लेषण करने में गलती की। खंड 2 (ए) और (बी) से पता चलता है कि केवल बी. ओ. क्यू. वस्तु, यानी तटबंध है। शर्त में अलग उपचार का मतलब केवल यह था कि तटबंध का निर्माण एक तरह से किया जा सकता था, जहां मिट्टी का उपयोग किया जाता था और दूसरा, जहां मिट्टी और तालाब की राख दोनों का उपयोग किया जाता था। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि तकनीकी विशिष्टताओं के खंड 305.8 के संदर्भ में, क्रॉस-सेक्शन को आनुपातिक रूप से मात्रात्मक रूप से संपादित किया जाना था। एसजी ने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि दो वर्षों के लिए, अलग-अलग माप लिए गए थे और परिणामस्वरूप यह तर्क देना गलत था कि दोनों सामग्रियों के लिए अलग-अलग माप संभव नहीं थे। यह आगे तर्क दिया गया कि तालाब की राख और मिट्टी के साथ तटबंध का काम जहां भी संबंधित सामग्री आवश्यक है और आसानी से मापने में सक्षम है, वहां परतों द्वारा पूरा किया जाता है। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि अलग-अलग मात्राओं को स्पष्ट रूप से अधिसूचित किया गया था और संबंधित शर्तों में उल्लेख किया गया था जिन्हें संबंधित समय पर पक्षकार अर्थ देने का इरादा रखते थे। इस पहलू को न्यायाधिकरण के एक सदस्य के असहमत पुरस्कार द्वारा उजागर किया गया था, जिन्होंने इस तरह की व्याख्या के आधार पर दावे को अस्वीकार करने के EE के फैसले को बरकरार रखा। इसलिए, जहां भी मिट्टी का उपयोग किया जाता था, उसे खंड 2 (ए) के अनुसार भुगतान किया जाता था और जहां भी तालाब की राख का उपयोग किया जाता था, भुगतान खंड 2 (बी) के अनुसार किया जाता था जिसे टी. एस. 305.2.2,3 के साथ पढ़ा जाता था। अंत में, यह तर्क दिया गया कि ड्राफ्ट्समैन का इरादा स्पष्ट था क्योंकि तकनीकी विशिष्टता के किसी भी संदर्भ को टाला गया था, लेकिन आई. आर. सी. का उल्लेख किया गया था: एसपी:58.201 और इसके बजाय केवल टीएस 305 और टीएस 305.2.2,3 का उपयोग किया गया था। इनमें फ्लैश और ऐश के साथ बनाए जाने वाले तटबंधों के बारे में बात या वर्णन नहीं किया गया था या यहां तक कि उन्हें समग्र तरीके से डिजाइन किया जाना चाहिए था।

14. एसजी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम श्री गणेश पेट्रोलियम राजगुरुनगर 8 पर भरोसा किया। पी. एस. ए. एस. आई. सी. ए. एल. टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम वी. ओ. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट का न्यासी मंडल 9; दक्षिण पूर्व एशिया समुद्री

8 2022 (16) एससीआर 450 9 2021 (5) एससीआर। 408

इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एस. ई. ए. एम. ई. सी. लिमिटेड) बनाम ऑयल इंडिया लिमिटेड 10

और अन्य निर्णय, एन. एच. ए. आई. के इस तर्क के समर्थन में कि यदि किसी न्यायाधिकरण द्वारा अपनाई गई व्याख्या कानून द्वारा असमर्थित है, या किसी मामले के दिए गए तथ्यों में पूरी तरह से गलत है, तो निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि जब तक संविदात्मक शर्तों की व्याख्या उचित और संभव है, पुरस्कारों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, यदि पुरस्कार इस तरह की व्याख्या को नहीं अपनाते हैं, और एक को अपनाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप किसी भी स्पष्ट संविदात्मक अवधि का अनुचित विस्तार होता है, तो उनमें हस्तक्षेप किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इस तरह के विवेकाधिकार के प्रयोग के अवसर का उपयोग विवादित निर्णय द्वारा सही ढंग से किया गया था।

विश्लेषण और निष्कर्ष

15. गुण-दोषों से निपटने से पहले, संबंधित अनुबंध की शर्तों को निकालना आवश्यक है। मुख्य निर्णय जिसमें कि. मी. 158 से कि. मी. 198 (गंगा पुल को छोड़कर) तक की सड़क के लिए इलाहाबाद बाईपास परियोजना के कार्यों का अनुबंध शामिल था, निम्नलिखित खंडों से संबंधित था:

वस्तु	वर्णन	इकाई	एस्ट। क्यूटी।	इकाई दर (आई.)	आईएनआर राशि
-------	-------	------	---------------	---------------	-------------

				एन. आर.)			
				शब्दों में कहें तो	इस तरह से	शब्दों में कहें तो	फाइगर्स में
2.02	तकनीकी विशिष्टता खंड 305 के अनुसार सभी लोड और लिफ्टों के साथ स्वीकृत सामग्री के साथ तटबंध का निर्माण						
	(a) मिट्टी के साथ	क्यूएम	1198000	रु. केवल एक सौ दो।	102	केवल बारह करोड़, इकतीस लाख छियानबे हजार।	122,196,000
	ख) तालाब की राख के साथ	क्यूएम	3252000	रु. केवल दो सौ पचास दो	252	केवल एक करोड़ नब्बे लाख चार लाख	819,504,000

10 2020 (4) एससीआर 254 633

मेसर्स हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड v.

मैसर्स नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया 634 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

16. बी. ओ. क्यू. मद संख्या 2 (बी) के तहत तालाब राख तटबंध के लिए, माप और भुगतान के लिए प्रासंगिक शर्त खंड 305.8 और खंड 305.2.3 क्रमशः अतिरिक्त तकनीकी विशिष्टताओं का। उक्त खंडों को नीचे निकाला गया है। एम. ओ. आर. टी. एच. की विशिष्टता इस प्रकार है:

“ 305.8 भुगतान के माप पृथ्वी तटबंध/उपश्रेणी निर्माण को काम शुरू होने से पहले और इसके पूरा होने के बाद मूल स्थिति में अंतराल पर क्रॉस सेक्शन लेकर और औसत अंतिम क्षेत्रों की विधि द्वारा घन मीटर में मिट्टी के कार्यों की मात्रा की गणना करके अलग से मापा जाएगा।”

खंड 305.2.2, 3.3- मद सं. 2 (ख) से संबंधित निम्नानुसार है:

“भुगतान के लिए मापन: एम. ओ. आर. टी. एच. विनिर्देशनों के खंड 305.8 के समान।”

दर अनुबंधों में अलग-अलग वस्तुओं के लिए अनुबंध दर इकाइयों के लिए प्रासंगिक शर्त खंड 114.1 है; यह निम्नानुसार है:

“ 114.1.- वस्तु दर अनुबंधों के लिए, काम की विभिन्न वस्तुओं के लिए अनुबंध इकाई दरों को "दरों" के तहत इन विशिष्टताओं के संबंधित अनुभागों में विस्तृत सभी कार्यों के लिए पूर्ण मुआवजे सहित विशिष्टताओं की आवश्यकताओं के अनुसार काम पूरा करने के लिए पूरा भुगतान किया जाएगा। इसके विपरीत किसी भी निर्देश के अभाव में, दरों को सभी श्रम, सामग्री, अपव्यय को शामिल करते हुए निष्पादित कार्य के लिए पूर्ण समावेशी दर माना जाना चाहिए। अनुबंध की सामान्य शर्तों से उत्पन्न होना।”

17. बहुमत पुरस्कार, मुख्य निर्णय में (जिससे सीए 4658/2023 उत्पन्न होता है) सूचीबद्ध करता है कि बहुमत में सदस्यों ने ठेकेदार के लिए क्यों पाया:

“i) अनुबंध में दो प्रकार के तटबंधों के निर्माण पर विचार किया गया है। एक अकेले मिट्टी के साथ, और दूसरा मिट्टी के तालाब की राख के संयोजन के साथ।

ii) अकेले तालाब की राख वाले तटबंध का निर्माण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तालाब की राख कटाव के लिए अतिसंवेदनशील है। इसलिए, तटबंध की सुरक्षा के लिए मिट्टी का आवरण प्रदान किया जाता है।

iii) बी. ओ. क्यू. मद संख्या 2 (बी) के तहत मिट्टी और तालाब की राख से युक्त तटबंध का समग्र क्रॉस सेक्शन को सामूहिक रूप से तालाब की राख के साथ तटबंध निर्माण कहा जाता है।

iv) मिट्टी या तालाब की राख के साथ तटबंध निर्माण के लिए भुगतान के लिए अपनाई जाने वाली माप की विधि एक ही है, जो कि समग्र क्रॉस सेक्शन को पूरे तटबंध के रूप में लेकर और औसत अंत क्षेत्र विधि द्वारा आयतन का निर्धारण करके है।

v) इंजीनियर द्वारा अपनाई गई माप की विधि, जिसमें, क्रॉस सेक्शन के क्षेत्र को मिट्टी और तालाब की राख द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र के लिए दो अलग-अलग वस्तुओं में तटबंध की मात्रा का निर्धारण करने के लिए विभाजित किया गया है, यदि तकनीकी विशिष्टता खंड 305.8 के विपरीत है।

vi) एम. ओ. आर. टी. एच. के खंड 114.1 में निर्दिष्ट रूप से कहा गया है कि दरें हर तरह से समाप्त किए गए काम के लिए हैं। तालाब की राख का तटबंध जिसमें मिट्टी और तालाब की राख शामिल है, मिश्रित और पूर्ण रूप से तैयार किया गया कार्य है। इसे दो अलग-अलग वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता है जैसा कि इंजीनियर द्वारा किया गया है।

vii) दावेदार का यह तर्क कि तालाब के राख तटबंध के पूरे क्रॉस सेक्शन को मद संख्या 2 (बी) के तहत काम के निर्धारण के लिए एक क्रॉस सेक्शन के रूप में मापा जाएगा, अनुबंध की शर्तों द्वारा पूरी तरह से समर्थित है।”

न्यायाधिकरण के सदस्य, जिन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ असहमति जताई, ने दर्ज किया कि विनिर्दिष्ट उद्धरणों का एक पठन:

“यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जहां भी मिट्टी का उपयोग किया जाता है, उसे 2.02 (ए) के तहत मापा जाएगा और जब भी तालाब की राख का उपयोग किया जाएगा तो इसे 2.02 (बी) के तहत टीएस 305.2.2.3 के साथ मापा जाएगा।

13.3.7 मैं दावे को अस्वीकार करते समय इंजीनियर द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हूं, क्योंकि इंजीनियर का विचार अनुबंध/बी. ओ. क्यू. प्रावधान के अनुसार है क्योंकि इस विशेष अनुबंध में मिट्टी और तालाब की राख के साथ तटबंध एक वस्तु के नीचे दिखाई देते हैं और अलग-अलग सामग्री के लिए बहुत स्पष्ट रूप से विभाजित होते हैं।

मेसर्स हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड v.

635

मेसर्स नेशनल हाईवाइज ऑथोरिटी ऑफ इंडिया 636 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

13.3.8 मैं इस बात का विश्लेषण करता हूं कि दावेदार ने मद संख्या 2 (बी) के तहत मिट्टी को भी राख के रूप में दावा करने के बारे में सोचा है। बी. ओ. क्यू.

13.3.9 इस प्रकार मैं यह निष्कर्ष निकालता हूं कि बी. ओ. क्यू. मद 2 (ए) और 2 (बी) में किया गया प्रावधान अलग-अलग सामग्री के लिए है अर्थात् 2 (ए) मिट्टी के लिए है और 2 (बी) तालाब की राख के लिए है और संबंधित वस्तुओं में उपयोग की जाने वाली सामग्री के प्रकार के लिए है।”

18. सी. ई. सी.-एच. सी. सी. (जे. वी.) 11; सनवे कंस्ट्रक्शन 12; पटेल के. एन. आर. जे. वी. 13; और ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स (पी) लिमिटेड (इसके बाद, "ओरिएंटल स्ट्रक्चर्स") जैसे अन्य ठेकेदारों के न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए पुरस्कारों में बहुमत पुरस्कार के समान तर्क को अपनाया गया, जो मुख्य निर्णय में जारी किया गया था। 14. कुछ मामलों में, शर्त निर्माण के लिए थी

एक "उधार क्षेत्रों से अनुमोदित सामग्री के साथ तटबंध" के संदर्भ में

टी. एस. खंड 305 का, और एफ. एल. वाई. के साथ एक तटबंध का निर्माण भी

कोयले या लिग्नाइट जलते थर्मल पावर स्टेशन से प्राप्त राख "(सीए)

4659/2023); इसी तरह, एफ. एल. वाई. ऐश या लिग्नाइट बर्निंग थर्मल स्टेशन अपशिष्ट पदार्थ के रूप में (सी. ए. 4660/2020); "सभी प्रकार की मिट्टी" और "एफ. एल. वाई. ऐश के साथ"

कोयले या लिग्नाइट जलते थर्मल पावर स्टेशन से "(CA 4661/2023) और

तालाब राख (CA 4662/2023)। 19. कुछ मामलों में, डी. आर. पी. (या डी. आर. बी.) ने विभागीय रूप से तीन विशेषज्ञों (सी. ए. 4659/2023 में) के साथ निम्नलिखित शब्दों में अपना विचार व्यक्त किया:

" 4.1.5.....उपरोक्त अनुबंध की शर्त का स्पष्ट रूप से अर्थ है कि तटबंध 6 या उपश्रेणी, जैसा भी मामला हो, को तटबंध का काम शुरू होने से पहले और उसके पूरा होने के बाद अंतराल पर क्रॉस सेक्शन लेकर अलग से मापा जाएगा। तटबंध का काम शुरू होने से पहले और पूरा होने के बाद 'क्रॉस सेक्शन लेना' वाक्यांश का उपयोग करने का अर्थ तटबंध को पूरी तरह से मापने के अलावा और कुछ नहीं है। दूसरे शब्दों में जिसे मापा जाना है वह एक तटबंध है और ऐसा माप तटबंध का काम शुरू होने से पहले और पूरा होने के बाद उपयुक्त अंतराल पर क्रॉस सेक्शन लेकर किया जाएगा।

काम का तटबंध। दूसरे शब्दों में, मात्रा

11 सीए में अपीलार्थी 4659/2023; सीए में 12 अपीलार्थी 4660/2023 13 सीए में अपीलार्थी 4661/2023 14 सीए में अपीलार्थी 4662/2023

अतिरिक्त तकनीकी विशिष्टता खंड ए-14 के अनुसार फ्लू याश और मिट्टी से बने पूरे तटबंध को मापा जाना है। हुआ था।

अनुबंध का उद्देश्य मिट्टी को अलग से मापना था, तो प्रत्येक मध्यवर्ती परत के क्रॉस सेक्शन को बार-बार मिट्टी के किनारे के आवरण के साथ कोर एफएलवाई ऐश के जंक्शन पर और एफएलवाई ऐश परत के शीर्ष पर भी 1 मीटर मिट्टी की परत से ढकना आवश्यक होगा, जो अनुबंध में भुगतान के लिए माप के तरीके में निर्धारित नहीं है। [...]

4.1.8 यह वस्तु फ्लू ऐश के साथ तटबंध के निर्माण के लिए है। शब्द "फ्लू ऐश के साथ" विशेषण के प्रकार को योग्य बनाते हैं।

तटबंध। इस प्रकार, यदि तटबंध को समग्र रूप से मापना आवश्यक है, न कि तटबंध वाली व्यक्तिगत सामग्री को। यदि वस्तु को "तटबंध के लिए राख प्रदान करने" के रूप में वर्णित किया गया होता तो केवल राख सामग्री को मापना उचित होता। अनुबंध का उद्देश्य तटबंध को मापना है। यह भी है

बी. ओ. क्यू. वस्तु no.2.02 (ए) के विवरण से पुष्टि की गई है, जो केवल एक प्रकार की सामग्री यानी अनुमोदित सामग्री में है; वर्णन में उपयोग किया जाने वाला वाक्यांश "अनुमोदित सामग्रियों के साथ तटबंध का निर्माण" है। यहाँ भी एक वस्तु के रूप में तटबंध और अनुमोदित सामग्री शब्द तटबंध के प्रकार को योग्य बनाने वाला विशेषण है।"

अन्य अपीलों में भी डी. आर. पी. ने इसी तरह के निर्देश दिए। ओरिएंटल स्ट्रक्चर्स (ऊपर) अपील (सी. ए. 4662/2023) में, डी. आर. बी. का निर्णय, अन्य बातों के साथ, यह था कि:

"डी. आर. बी. का निर्णय तालाब ऐश तटबंध के लिए मिट्टी के आवरण और तालाब ऐश को एक साथ मापना है और बी. ओ. क्यू. मद 02 (बी) के तहत भुगतान किया जाना है। बी. ओ. क्यू. मद 02 (बी) के तहत वित्तीय राशि इंजीनियर के पास है और इसे नियोजित को प्रस्तुत किया जाएगा और ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई छूट की अनुमति देने के बाद के दिनों में प्रचलित मध्यस्थता के बाद अनुमोदित दरों पर भुगतान किया जाएगा।"

20. यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ज्यादातर मामलों में, डी. आर. पी. और न्यायाधिकरणों के विचार, और दो मामलों में, न्यायाधिकरणों के बहुमत ने ठेकेदारों के तर्कों का समर्थन किया, कि समग्र तटबंध निर्माण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप माप एक समग्र, या एकीकृत तरीके से किया जाना था। असहमति या अल्पमत के विचार, जहां भी व्यक्त किए गए थे, 637 पर आधारित थे।

मेसर्स हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड v.

अलग मापायह राय मध्यस्थों के रूप में गठित तकनीकी विशेषज्ञों की थी, जो शामिल कार्य के प्रकार की संविदात्मक व्याख्या में पारंगत थे; उन्हें ऐसे अनुबंधों की देखरेख करने वाले इंजीनियरों के रूप में भी पहला अनुभव था। जब इन विशेषज्ञों के प्रमुख दृष्टिकोण ने एक दिशा, यानी एक समग्र माप की ओर इशारा किया, तो सवाल यह है कि अधिनियम की धारा 34 के तहत अदालत की वास्तव में क्या भूमिका है।

21. यह अदालत, मैसर्स वोएस्टाल्पाइन शियनन जीएमबीएच बनाम डीएमआरसी 15 में

मध्यस्थ के रूप में विशेषज्ञ कर्मियों के होने के मूल्य पर टिप्पणी करते हुए,

इस बात पर जोर दिया कि "विवाद के तकनीकी पहलुओं को उनकी विशेषज्ञता का उपयोग करके उचित रूप से हल किया जाता है जब वे मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं।" दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस (पी) लिमिटेड बनाम डीएमआरसी 16 में भी इस तरह के दृष्टिकोण की सराहना की गई थी।

जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

“मध्यस्थ न्यायाधिकरण के सदस्य, पक्षों के बीच सहमत प्रक्रिया के अनुसार नामित, इंजीनियर हैं और उनके पुरस्कार की उसी तरीके से जांच नहीं की जानी चाहिए जिस तरह से कानूनी रूप से प्रशिक्षित दिमागों द्वारा तैयार किया जाता है। किसी भी स्थिति में, यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण विकृत है। इसलिए, हम उच्च न्यायालय की इस राय से सहमत नहीं हैं कि समाप्ति नोटिस की वैधता पर न्यायाधिकरण का निर्णय विकृति के कारण दूषित है।”

22. न्यायिक समीक्षा के मानक के बारे में प्रचलित दृष्टिकोण-न कि न्यायिक समीक्षा, एक पुरस्कार के बारे में, विवादित व्यक्तियों की पसंद के व्यक्तियों द्वारा खड़े होने और हस्तक्षेप न करने के उनके निर्णयों के बारे में, [एक छोटे से क्षेत्र को छोड़कर जहां यह स्थापित किया गया है कि ऐसा दृष्टिकोण पेटेंट अवैधता या तथ्यों या शर्तों की उनकी व्याख्या पर आधारित है, विकृत, हस्तक्षेप के लिए अर्हता प्राप्त करने के रूप में, अदालतों को आवश्यक रूप से कम से कम हस्तक्षेप का मार्ग चुनना होगा, सिवाय इसके कि जब बिल्कुल आवश्यक हो]। प्रशिक्षण, झुकाव और अनुभव से, न्यायाधीश एक सुधारात्मक लेंस को अपनाते हैं; आमतौर पर, अपीलीय समीक्षा के लिए सराहा जाता है। हालांकि, अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय वह लेंस उपलब्ध नहीं है।

अधिनियम की धारा 34 के तहत। न्यायालय, प्राथमिक अनुबंध व्याख्या की प्रक्रिया के माध्यम से, इस प्रकार, समीक्षा के लिए मार्ग नहीं बना सकते हैं जो

धारा 34 के तहत वर्जित है। इस प्रकार देखे जाने पर, अपीलीय समीक्षा के डिवीजन बेंच के दृष्टिकोण को दो बार हटा दिया गया, इसलिए कहें कि [धारा 37 के तहत], और

15 2017 (1) एससीआर 798 16 2021 (5) एससीआर 984

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

इसके द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के परिणामस्वरूप न्यायाधिकरण के बहुमत के दृष्टिकोण को विस्थापित किया गया, और कई मामलों में, अन्य न्यायाधिकरणों के सर्वसम्मत दृष्टिकोण और दूसरे दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित किया गया। जब तक बहुमत द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण प्रशंसनीय था-और इस अदालत को अन्यथा ठहराने का कोई कारण नहीं था (क्योंकि माना जाता है कि काम पूरा हो गया था और पक्का तटबंध मिश्रित, सघन पदार्थ से बना था, जिसमें मिट्टी और राख दोनों शामिल थे), इस तरह का प्रतिस्थापन अस्वीकार्य था।

23. लंबे समय से, यह देश में अदालतों का स्थापित न्यायशास्त्र है कि जिन पुरस्कारों में कारण होते हैं, विशेष रूप से जब वे संविदात्मक शर्तों की व्याख्या करते हैं, उनमें हल्के में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। यह प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम संबद्ध निर्माण 17 में रखा गया था:“[.....] समझौते में प्राप्त तथ्य-स्थिति को ध्यान में रखते हुए समझौते के खंड 47 की व्याख्या करना उनके अधिकार क्षेत्र में था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय या तो कानून के आधार पर गलत हो सकता है या तथ्य और कानून की त्रुटि के आधार पर गलत हो सकता है क्योंकि यह किसी निर्णय को रद्द नहीं कर सकता है। पुरस्कार एक बोलने वाला पुरस्कार है। मध्यस्थ ने इसके समर्थन में पर्याप्त और ठोस कारण दिए हैं। किसी अनुबंध की व्याख्या, जो साधारण है, मध्यस्थ को निर्धारित करने का विषय है (देखें मेसर्स सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी बनाम केरल सरकार, आकाशवाणी (1989) एससी 890)। मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 30, जिसमें किसी पुरस्कार को अलग रखने का प्रावधान है, उसके संचालन में प्रतिबंधात्मक है। जब तक धारा 30 में निहित एक या दूसरी शर्त को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक किसी पुरस्कार को अलग नहीं किया जा सकता है। मध्यस्थ पक्षकारों द्वारा चुना गया न्यायाधीश होता है और उसका निर्णय अनिवार्य होता है। न्यायालय को साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने से रोक दिया गया है। यहां तक कि ऐसे मामले में भी जहां पुरस्कार में कारण शामिल हैं। इसके साथ हस्तक्षेप तब भी न्यायालय की अधिकारिता के भीतर उपलब्ध नहीं होगा जब तक कि, निश्चित रूप से, कारण पूरी तरह से विकृत न हों या निर्णय कानून के गलत प्रस्ताव पर आधारित न हो।

24. इस कथन का कई मामलों में समर्थन किया गया है (संदर्भ

मैकडरमोट इंटरनेशनल इंक. बनाम बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड 18)। एमएसके परियोजनाओं में

(I) (जेवी) लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य 19 यह अभिनिर्धारित किया गया कि व्याख्या में त्रुटि है।

17 2003 सप्लीमेंट (2) एससीआर 55 18 2006 सप्लीमेंट (2) एस. सी. आर. 409 19 2011 (9) एस. सी. आर. 402 239

मेसर्स हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड v.

मेसर्स नेशनल हाईवाइज ऑथोरिटी ऑफ इंडिया [एस. रवींद्र भाट, जे.] 640 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

एक मध्यस्थ द्वारा एक अनुबंध का "उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर एक त्रुटि" है। द.

एसोसिएट बिल्डर्स (ऊपर) में स्थिति को और भी स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया था, जहाँ अदालत ने कहा था कि:

“[.....] यदि कोई मध्यस्थ अनुबंध की अवधि को उचित तरीके से समझता है, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि पुरस्कार को इस आधार पर अलग रखा जा सकता है। अनुबंध की शर्तों का निर्माण मुख्य रूप से एक मध्यस्थ को यह तय करना है कि जब तक मध्यस्थ अनुबंध का इस तरह से अर्थ नहीं निकालता है कि इसे कुछ ऐसा कहा जा सकता है जो कोई निष्पक्ष या उचित व्यक्ति नहीं कर सकता है।”

25. चर्चा समाप्त करने से पहले, एक ऐसे पहलू पर प्रकाश डालना भी आवश्यक होगा जो कुछ मध्यस्थता कार्यवाही में उत्पन्न होने की संभावना है, विशेष रूप से जब इसमें बहु-सदस्यीय न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय शामिल हो। इस पहलू को रसेल ऑन आर्बिट्रेशन में उजागर किया गया था, जहां एक असहमत राय की प्रासंगिकता को निम्नानुसार समझाया गया था [जैसा कि दक्षिण हरियाणा में उद्धृत किया गया है।

बिजली वितरण निगम लिमिटेड बनाम. नेविगेंट टेक्नोलॉजीज (पी) लिमिटेड (इसके बाद, "दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड") 20:

“6-058. असहमतिपूर्ण राय।—न्यायाधिकरण का कोई भी सदस्य जो किसी पुरस्कार के लिए सहमति नहीं देता है, उसे उस पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह या तो पुरस्कार दस्तावेज के भीतर या एक अलग "असहमत राय" में मामले के बारे में अपने विचार रख सकता है। मध्यस्थ को सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए कि क्या अपनी असहमति व्यक्त करने का कोई अच्छा कारण है, क्योंकि एक असहमत राय पुरस्कार को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। यह केवल पक्षों की जानकारी के लिए है और पुरस्कार का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह किसी चुनौती की स्थिति में प्रक्रियात्मक मामलों के संबंध में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हो सकता है या पुरस्कार के खिलाफ अपील करने के इच्छुक पक्ष की दलीलों को महत्व दे सकता है।” 21

इस अदालत ने अंतर्राष्ट्रीय पर गैरी बी. बोरन की टिप्पणी को भी उद्धृत किया।

21 डेविड सेंट जॉन सटन, जूडिथ गिल और मैथ्यू गियरिंग क्यूसी, रसेल ऑन आर्बिट्रेशन, 24 वीं संस्करण। (स्वीट और मैक्सवेल), पृ. 313.

22 गैरी बोर्न, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, वोल्टर्स क्लूवर, एडन। 2009, वॉल्यूम। II, पी. 2466 और 2469।

“राष्ट्रीय कानून या लागू संस्थागत नियमों (या अन्यथा) में व्यक्त प्राधिकरण के अभाव में भी, असहमति या अलग राय प्रदान करने का अधिकार मध्यस्थ के निर्णयात्मक कार्य और एक तर्कपूर्ण निर्णय देने के लिए न्यायाधिकरण के संबंधित दायित्व का एक उपयुक्त सहवर्ती है। हालाँकि ऐसी कानूनी प्रणालियाँ हैं जहाँ असहमति या अलग-अलग राय की या तो अनुमति नहीं है, या प्रथागत नहीं है, इन घरेलू नियमों का पक्ष-नामित सह-मध्यस्थों और विविध न्यायाधिकरणों के संदर्भ में बहुत कम अनुप्रयोग है। वास्तव में, एक मध्यस्थ के असहमतिपूर्ण राय देने के अधिकार को उचित रूप से उसके न्यायिक जनादेश का एक तत्व माना जाता है, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जहाँ एक तर्कपूर्ण पुरस्कार की आवश्यकता होती है। केवल स्पष्ट निषेध को असहमति रखने वाले पक्षों को राय बनाने और प्रकाशित करने से रोकना चाहिए, जो विचार-विमर्श प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और मनमाने या असमर्थनीय निर्णय लेने पर एक मूल्यवान नियंत्रण प्रदान कर सकता है। [.]

[...]

एक मध्यस्थ के बारे में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है “व्यवस्थित रूप से एक असहमत राय तैयार करना, और इस बात पर जोर देना कि इसे पक्षों को सूचित किया जाए”। यदि कोई मध्यस्थ मानता है कि न्यायाधिकरण गंभीर रूप से गलत निर्णय ले रहा है, जिसका कानून और साक्ष्य रिकॉर्ड के साथ उचित रूप से मिलान नहीं किया जा सकता है, तो वह उस विचार को व्यक्त कर सकता है। न्यायनिर्णायक प्रक्रिया एकटा हिस्साक रूपमे, जाहिमे न्यायाधिकरणक निष्कर्ष तर्कपूर्ण ढंगसे व्यक्त कयल जाइत अछि, किछु गलत नहि अछि-आ एकर विपरीत, बहुत किछु सही अछि। और, यदि मध्यस्थ यह मानता है कि पुरस्कार के निष्कर्षों के लिए एक “व्यवस्थित” चर्चा की आवश्यकता है, तो यह भी पूरी तरह से उचित है; वास्तव में, यह निर्णय प्रक्रिया में निहित है, और एक तर्कपूर्ण पुरस्कार की आवश्यकता है।”

[...]

... एक बहु-सदस्य न्यायाधिकरण द्वारा एक तर्कपूर्ण निर्णय की अवधारणा अलग-अलग कारणों के बयान की अनुमति देती है- यदि न्यायाधिकरण के अलग-अलग सदस्य वास्तव में अलग-अलग विचार रखते हैं। यह उस प्रक्रिया का एक अनिवार्य पहलू है जिसके द्वारा पक्षों को दोनों के लिए, अपना मामला प्रस्तुत करने और न्यायाधिकरण के निर्णय के कारणों को सुनने का अवसर मिलता है; असहमति को न सुनना पक्षों को इस प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण पहलू से वंचित करता है।”

मेसर्स हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड v.

641

मेसर्स नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया [एस. रवींद्र भाट, जे.] 642

26. दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में, अदालत ने सांगयोंग इंग में पिछली हिस्सेदारी को याद किया। & कंस्ट्रक्शन कं. लिमिटेड बनाम एन. एच. ए. आई. (इसके बाद, “सांगयोंग एंग। & निर्माण कंपनी लिमिटेड”) 23, जिसमें

अदालत ने बहुमत के फैसले को दरकिनार कर दिया था, लेकिन मामले के विशिष्ट तथ्यों में परिणामी निर्देश जारी किए:

“सांगयोंग में [सांगयोंग एंग। & कंस्ट्रक्शन कं. लिमिटेड बनाम एन. एच. ए. आई., (2019) 7 एस. सी. आर. 522], इस न्यायालय ने पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए असंतुष्ट मध्यस्थ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को बरकरार रखा। ऐसा करने का कारण पैरा 77 में उल्लिखित है अर्थात् काफी देरी जो एक और मध्यस्थता आयोजित होने पर होगी। इस न्यायालय ने सांगयोंग [सांगयोंग एंग.] में अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग किया। & कंस्ट्रक्शन कं. लिमिटेड बनाम एन. एच. ए. आई.,] मामले के तथ्यों और मध्यस्थता अधिनियम के तहत विवादों के त्वरित समाधान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए।

हालांकि, अदालत ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम मामले में ऐसा नहीं किया।

लिमिटेड (सुप्रा) असहमत राय को एक पुरस्कार के रूप में माने जाने का निर्देश देता है। इस अदालत की राय में, यह दृष्टिकोण सही है, क्योंकि रसेल और गैरी बॉर्न के बीच सोच में थोड़ा अंतर प्रतीत होता है। पूर्ववर्ती, रसेल यह इंगित करने में सावधानी बरतते हैं कि एक असहमत राय प्रति नहीं है।

एक पुरस्कार है, लेकिन "केवल पक्षों की जानकारी के लिए है और पुरस्कार का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह एक चुनौती की स्थिति में प्रक्रियात्मक मामलों के संबंध में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हो सकता है।" हालांकि, गैरी बॉर्न करते हैं

यह स्पष्ट रूप से न कहें कि राय पुरस्कार का हिस्सा नहीं है। वह लेखक अभी तक

यह स्पष्ट किया जाता है कि "यह उस प्रक्रिया का एक अनिवार्य पहलू है जिसके द्वारा पक्षों को दोनों के लिए एक अवसर मिलता है, अपना मामला प्रस्तुत करता है, और न्यायाधिकरण के निर्णय के कारणों को सुनता है; असहमति को नहीं सुनना पक्षों को इस प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण पहलू से वंचित करता है।"

27. इसलिए, यह स्पष्ट है कि यदि बहुमत पुरस्कार को अलग रखा जाता है तो असहमत राय को पुरस्कार के रूप में नहीं माना जा सकता है। यदि कोई प्रक्रियात्मक मुद्दा है जो चुनौती सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण हो जाता है तो यह उपयोगी सुराग प्रदान कर सकता है। इस अदालत की राय है कि इस मामले में एक और आयाम है। जब पीड़ित पक्ष द्वारा बहुमत पुरस्कार को चुनौती दी जाती है,

23 2019 [7] एससीआर 522

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

अदालत और पीड़ित पक्ष का ध्यान बहुमत पुरस्कार में त्रुटियों या अवैधताओं को इंगित करना है। अल्पमत पुरस्कार (या असहमतिपूर्ण राय, जैसा कि विद्वान लेखक बताते हैं) केवल मध्यस्थ के विचारों का प्रतीक है जो बहुमत से असहमत हैं। किसी के लिए भी कोई अवसर नहीं है—जैसे कि बहुमत पुरस्कार से व्यथित पार्टी, या, अधिक महत्वपूर्ण रूप से, वह पार्टी जो

बहुमत पुरस्कार में सफल होता है, दृढ़ता, संभाव्यता को चुनौती देने के लिए,

असहमत राय में दृष्टिकोण या निष्कर्ष में अवैधता या विकृति। उस असहमत राय को जांच के स्तर और मानक प्राप्त नहीं होंगे जो बहुमत पुरस्कार (जो चुनौती के अधीन है) के अधीन है।

इसलिए, असहमत राय का एक न्यायाधिकरण में तथाकथित रूपांतरण।

[बहुमत पुरस्कार अलग रखे जाने की स्थिति में] और उस राय को पुरस्कार के रूप में ऊपर उठाना, सम्मान के साथ, अनुचित और अनुचित होगा। 28. पहले दर्ज किए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, इस अदालत की राय है कि सभी अपीलों को सफल होना होगा। अतः, सी. ए. सं. 4658/2023, सी. ए. सं. 4659/2023; सी. ए. नं. 4660/2023; सी. ए. सं. 4661/2023 और सी. ए. सं. 4662/2023 की अनुमति है। दिल्ली उच्च न्यायालय के सभी निर्णय, जो उन अपीलों में चुनौती का विषय थे, खारिज कर दिए जाते हैं। पुरस्कार, जो चुनौती का विषय थे, और जिस हद तक उन्हें अलग रखा गया था, उन्हें एतद्वारा बरकरार रखा जाता है और बहाल किया जाता है। पुरस्कारों में निर्देश, जिस हद तक उन्हें चक्रवृद्धि मासिक ब्याज भुगतान की आवश्यकता होती है, को संशोधित किया जाता है। इसके बजाय, एनएचआई आज से आठ सप्ताह के भीतर संबंधित शीर्ष पर देय राशि, यानी तटबंध के निर्माण पर, पुरस्कार की तारीख से भुगतान की तारीख तक 12 प्रतिशत की सीमा तक समान ब्याज का भुगतान करेगा। उपरोक्त सभी अपीलों की इन शर्तों में अनुमति है। लागत का भुगतान करने का कोई निर्देश नहीं होगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपीलों की अनुमति दी गई।

निधि जैन

